



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 527]
No. 527]

नई दिल्ली, बुधस्तिवार, अक्टूबर 30, 2003/कार्तिक 8, 1925
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 30, 2003/KARTIKA 8, 1925

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2003

सा.का.नि. 853(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में और संशोधन हेतु निम्नांकित योजना बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधित शर्तें) योजना, 2003 कहा जाएगा।
(2) यह योजना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।
- वर्तमान परिशिष्ट-क के स्थान पर कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 27कक में निम्नांकित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परिशिष्ट क”

कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अन्तर्गत छूट प्रदान करने हेतु संशोधित शर्तें अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत छूट प्रदान करने हेतु संशोधित शर्तें निम्नवत् हैं :

- केन्द्र सरकार या केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (जैसा भी मामला हो) द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशानुसार भविष्य निधि के प्रबन्धन हेतु नियोक्ता अपनी अध्यक्षता में न्यासी बोर्ड की स्थापना करेगा। भविष्य निधि, न्यासी बोर्ड के अधीन रहेगी जो भविष्य निधि में प्राप्त और इससे अदा की गई एवं अपनी अभिरक्षा में शेष राशि के उचित लेखे रखने के साथ-साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रति जिम्मेदार तथा संगठन को जवाबदेह होगा। इस प्रयोजनार्थ, “नियोक्ता” का अर्थ है—
(i) प्रतिष्ठान (कारखाना) के संदर्भ में, कारखाने का स्वामी या अधिष्ठाता; तथा
(ii) किसी अन्य प्रतिष्ठान के संदर्भ में, प्रतिष्ठान के कामकाज पर अंतिम रूप से नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति या प्राधिकारी।
- न्यासी बोर्ड हर तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगा और केन्द्र सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उनके द्वारा

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।

3. अधिनियम की धारा 2(च) में यथापरिभाषित ऐसे हर कर्मचारी सदस्य के रूप में शामिल किए जाएंगे जो प्रतिष्ठान द्वारा छूट न दिए जाने की वजह से भविष्य निधि के सदस्य बनने की पात्रता रखते हैं।
4. यदि कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि या किसी छूट प्राप्त प्रतिष्ठान की भविष्य निधि का सदस्य हो, तो नियोक्ता प्रतिष्ठान में उसके नियोजित होने पर उसे तुरन्त, निधि के सदस्य के रूप में दर्ज करेगा। नियोक्ता ऐसे कर्मचारी के पूर्ववर्ती नियोक्ता के पास उसके भविष्य निधि खाते में जमा राशि अंतरित कराने और उसके खाते में जोड़ने की व्यवस्था भी करेगा।
5. नियोक्ता, अधिनियम के तहत समय-समय पर यथानिर्धारित दर के अनुसार स्वयं तथा कर्मचारियों द्वारा देय अंशदान, जिस माह के लिए अंशदान दिया गया हो, उसके अगले माह की 15 तारीख तक, न्यासी बोर्ड को अंतरित करेगा। किसी बकाया के भुगतान में विलम्ब के लिए अधिनियम की धारा 7थ के उपबंधों के अनुसार साधारण ब्याज न्यासी बोर्ड में जमा करने का उत्तरदायित्व नियोक्ता का होगा।
6. नियोक्ता, भविष्य निधि के प्रशासन संबंधी समस्त व्ययों को वहन करेगा और चोरी, सेंधमारी, गबन, दुर्नियोजन या किसी अन्य कारणवश भविष्य निधि को हुए किसी अन्य घाटे की भरपाई भी करेगा।
7. नियोक्ता, न्यासी बोर्ड द्वारा घोषित ब्याज में किसी प्रकार की कमी की भरपाई करेगा ताकि इसे सांविधिक सीमा तक लाया जा सके।
8. नियोक्ता, समुचित प्राधिकारी द्वारा यथाअनुमोदित तथा यथासंशोधित निधियों के नियमों की प्रति (अधिसंख्यक कर्मचारियों की भाषा में अनुवाद सहित) प्रतिष्ठान के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा।
9. प्रतिष्ठान के भविष्य निधि नियमों के तहत निर्धारित देय अंशदान की दर, अग्रिमों की शर्तें और परिमाण तथा अन्य मामले और प्रत्येक सदस्य के खाते में जमा ब्याज सदस्य के मासिक शेष के आधार पर आकलित तथा न्यासी बोर्ड के द्वारा घोषित राशि, अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनी योजनाओं में निर्धारित विभिन्न उपबंधों के तहत केन्द्र सरकार द्वारा घोषित राशि से कम नहीं होगी।
10. प्रतिष्ठान के मौजूदा नियमों से कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी, योजना में किया गया हर संशोधन न्यास के नियमों में औपचारिक संशोधन किए जाने तक उन पर स्वतः अनुप्रयोग्य होगा।
11. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एतदुपरांत क्षे.भ.नि.आ. के रूप में उल्लिखित) के पूर्वानुमोदन के बिना नियोक्ता नियमों में कोई संशोधन नहीं करेगा। अनुमोदन करने से पूर्व, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कर्मचारियों को अपने विचार रखने का उपयुक्त अवसर देंगे।
12. आहरण, अग्रिम तथा अंतरण संबंधी सभी दावे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित अधिकतम समय-सीमा के भीतर ही शीघ्रता से निपटाए जाएंगे।
13. न्यासी बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में जमा अंशदान, आहरण तथा ब्याज को दर्शाने वाला विस्तृत लेखा रखेगा। ऐसे अभिलेखों का यथासंभव, इलेक्ट्रॉनिक रूप से रख-रखाव किया जाना चाहिए। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से निदेश प्राप्त होने पर, प्रतिष्ठानों को सदस्य के लेखों का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, आवधिक तौर पर, प्रेषण करना होगा।
14. न्यासी बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वित्तीय/लेखा वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर वार्षिक लेखा विवरणी या पास बुक प्रतिवर्ष एक बार निःशुल्क जारी करेगा। सदस्य की मांग पर नाममात्र के शुल्क पर अतिरिक्त मुद्रित प्रतियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं। पास बुक कर्मचारी के पास रहेगा और जिसे प्रस्तुत किए जाने पर न्यासी आवधिक रूप से उन्हें अद्यतन करेगा।
15. सदस्यों के चाहने पर, नियोक्ता उन्हें अपनी शेष राशि को कम्प्यूटर टर्मिनल पर दिखाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा।
16. न्यासी बोर्ड और नियोक्ता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा यथानिर्धारित मासिक/वार्षिक विवरणी निर्धारित समय-सीमा के भीतर जमा करेगा अन्यथा इसे चूक माना जाएगा तथा न्यासी बोर्ड और नियोक्ता संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की उपयुक्त दंडिक कार्रवाई के भागीदार होंगे।
17. न्यासी बोर्ड, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार भविष्य निधि की राशि का निवेश करेगा। सरकार के निदेशों के अनुसार निवेश करने में विफल रहने पर न्यासी बोर्ड पृथक-पृथक तथा संयुक्त रूप से, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उनके

प्रतिनिधि द्वारा लगाए गए अधिभार का भागीदार होगा।

18. (क) प्रतिभूतियाँ, न्यास के नाम पर प्राप्त की जाएंगी। इस प्रकार प्राप्त प्रतिभूतियाँ (डीमेट) रूप में होनी चाहिए और यदि न्यास के प्रचालन वाले क्षेत्रों में अपेक्षित सुविधा उपलब्ध न हो, तो न्यासी बोर्ड इस बारे में संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को सूचित करेगा।
- (ख) न्यासी बोर्ड स्क्रिप्टवार पंजी रखेगा और ब्याज की सामान्य वसूली सुनिश्चित करेगा।
- (ग) डीमेट खाता, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अनुदेशों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित जमाकर्ता सहभागियों के जरिए ही खोला जाना चाहिए।
- (घ) डीमेट खाता रखने पर आने वाली लागत को न्यास द्वारा निवेश की आकस्मिक लागत माना जाएगा। साथ ही, प्रतिभूति आदि की खरीद के लिए दलाली जैसे निवेशों की हर प्रकार की लागत को न्यास द्वारा निवेश की आकस्मिक लागत माना जाएगा।
19. प्रतिभूतियों और बांडों की खरीद जैसे सभी निवेश, भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित जमाकर्ता सहभागियों की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे जो उनके अभिरक्षक होंगे। प्रतिष्ठान की बंदी या परिसमापन या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 से प्राप्त छूट को निरस्त किए जाने पर, ऐसा अभिरक्षक न्यास के नाम पर प्राप्त निवेश (जो इसके ही नाम जमा हो) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से इस आशय का अनुरोध प्राप्त होने पर सीधे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को अंतरित करेगा।
20. छूट प्राप्त प्रतिष्ठान उन जमाकर्ता सहभागियों (भारतीय रिजर्व बैंक तथा केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित) से सम्बद्ध विवरण संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को भेजेगा जिसके पास और जिनकी सुरक्षित अभिरक्षा में न्यास के नाम पर किए गए निवेश, जैसे प्रतिभूतियाँ, बांड आदि हों। तथापि, न्यासी बोर्ड दावों के निपटान, नियमानुसार अग्रिम की मंजूरी तथा नियोक्ता की सेवा छोड़ने की स्थिति में सदस्य की भविष्य निधि जमा के अंतरण एवं प्रतिभूतियों की बिक्री से हुई कोई अन्य प्राप्तियों या निधि के नाम हुए अन्य निवेशों आदि जैसे अनिवार्य व्ययों की पूर्ति के लिए, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से पूर्वानुमोदन लेकर राशि या धनराशि एकत्रित कर सकता है।
21. न्यास द्वारा किए गए निवेश हेतु किसी भी वित्तीय या अन्य संस्थानों द्वारा दिया गया हर प्रकार का कमीशन, प्रोत्साहन राशि, बोनस या अन्य आर्थिक पुरस्कार इसके खाते में जमा किया जाना चाहिए।
22. छूट दिए जाने समय नियोक्ता तथा न्यासी बोर्ड के सदस्यगण समय-समय पर यथानिर्धारित प्रारूप में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को इस आशय का एक लिखित वचनबंध भी देंगे कि वे विनिर्दिष्ट शर्तों या छूट को जारी रखने के लिए बाद में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करेंगे और यह नियोक्ता तथा न्यासी बोर्ड (उनके उत्तराधिकारियों और समनुदेशितियों सहित) पर कानूनन बाध्यकारी होगा।
23. छूट रद्द किए जाने की स्थिति में नियोक्ता और न्यासी बोर्ड भी, संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर निधि को तत्परतापूर्वक अंतरित करने के लिए वचनबंध देगा। यह उन पर कानूनन बाध्यकारी होगा और निधियों के अंतरण में किसी भी प्रकार के विलम्ब की स्थिति में उन्हें अभियोजन का भागीदार बनाएगा।
24. (क) न्यासी बोर्ड द्वारा रखी जाने वाली भविष्य निधि खाते की एक स्वतंत्र व योग्य चार्टर्ड लेखाकार द्वारा वार्षिक रूप से लेखापरीक्षा की जाएगी। यदि आवश्यक समझा जाए, तो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या क्षेत्र के प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को खाते की, किसी अन्य योग्य लेखा परीक्षक से पुनः लेखापरीक्षा करवाने का अधिकार होगा और इस प्रकार हुआ व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा।
- (ख) लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के साथ अपनी रिपोर्ट की एक प्रति 01 अप्रैल से 31 मार्च के वित्त वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर सीधे संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को भेजेगा। तुलन पत्र का प्रारूप और रिपोर्ट में दी जाने वाली सूचना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा यथानिर्धारित के अनुसार होगी और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक रूप में तथा हस्ताक्षरित मुद्रित/अंकित प्रति के साथ उपलब्ध कराई जाएगी।
- (ग) दो लगातार वर्षों के लिए तथा छह वर्षों के ब्लॉक में दो वर्ष से ज्यादा के लिए एक ही लेखा परीक्षक की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए।

25. तीन लगातार वित्त वर्ष तक घाटे की या पूंजी आधार में कमी आने की रिपोर्ट देने वाली कम्पनी की छूट अगले उत्तरवर्ती वित्त वर्ष के पहले दिन से वापस ले ली जाएगी।
26. छूट प्राप्त प्रतिष्ठान के मामले में, नियोक्ता अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए निदेशानुसार निरीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और ऐसे निरीक्षणों के प्रभार का प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान करेगा।
27. नियोक्ता या न्यासी बोर्ड द्वारा छूट संबंधी शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात्, की गई छूट को रद्द किया जा सकता है।
28. जालसाजी, गबन, निवेश संबंधी गलत निर्णयों आदि के कारण न्यास को किसी प्रकार का नुकसान होने पर नियोक्ता घाटे की भरपाई का उत्तरदायी होगा।
29. आयोजन, विलगन, अधिग्रहण, बिक्री, समायोजन, सहायक प्रतिष्ठान के निर्माण (चाहे पूर्ण स्वामित्व वाला हो या नहीं) के कारण छूट प्राप्त प्रतिष्ठान की विधिक स्थिति में परिवर्तन की दशा में, दी गई छूट वापस ले ली गई समझी जाएगी तथा प्रतिष्ठान को नये सिरे से छूट प्राप्त करने के लिए इस मामले की रिपोर्ट तुरन्त संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को देनी चाहिए।
30. यदि सामान्य भविष्य निधि न्यास में सहभागिता करने वाले छूट प्राप्त इकाई/प्रतिष्ठान की संख्या एकाधिक हो, तो किसी भी न्यासी/किसी भी सहभागी इकाई के नियोक्ता द्वारा की गई किसी भी प्रकार की चूक के लिए सभी न्यासी संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक उत्तरदायी होंगे तथा सामान्य भविष्य निधि न्यास के समस्त न्यासियों के विरुद्ध क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त उपयुक्त निरीक्षक कार्रवाई करेगा।
31. प्रतिष्ठानों को छूट जारी रखने के लिए केन्द्र सरकार आगे भी शर्तें तय कर सकती है।

[फा. सं. एस-35016/01/2002-एस.एस.-II]

डी.एस. पूनिया, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में समय-समय पर संशोधन किया गया है; इसके पिछले संशोधन को भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 783(अ) दिनांक 6-10-2003 द्वारा अधिचित किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2003

G.S.R. 853(E).— In exercise of the powers conferred by section 5, read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 namely:-

1. (1) This Scheme shall be called the Employees' Provident Funds (Amended conditions) Scheme, 2003.
(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the official Gazette.
2. In paragraph 27 AA of Employees' Provident Funds Scheme, 1952 for the existing Appendix-A, the following Appendix shall be substituted, namely:-

"Appendix 'A'**Revised Conditions for Grant of Exemption under Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.**

The following are the revised conditions for grant of exemption under section 17 of the Act, 1952:-

1. The employer shall establish a Board of Trustees under his Chairmanship for the management of the Provident Fund according to such directions as may be given by the Central Government or the Central Provident Fund Commissioner, as the case may be, from time to time. The Provident Fund shall vest in the Board of Trustees who will be responsible for and accountable to the Employees' Provident Fund Organization, inter alia, for proper accounts of the receipts into and payment from the Provident Fund and the balance in their custody. For this purpose, the "employer" shall mean -
 - (i) in relation to an establishment, which is a factory, the owner or occupier of the factory; and
 - (ii) in relation to any other establishment, the person who, or the authority, that has the ultimate control over the affairs of the establishment.
2. The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/ Central Provident Fund Commissioner (CPFC) or an officer authorized by him.
3. All employees, as defined in section 2(f) of the Act, who have been eligible to become members of the Provident Fund, had the establishment not been granted exemption, shall be enrolled as members.
4. Where an employee who is already a member of Employees' Provident Fund or a provident fund of any other

3194 GI/03-2

exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the fund. The employer should also arrange to have the accumulations in the provident fund account of such employee with his previous employer transferred and credited into his account.

5. The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the Provident Fund by himself and employees at the rate prescribed under the Act from time to time by the 15th of each month following the month for which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay simple interest in terms of the provisions of section 7Q of the Act for any delay in payment of any dues towards the Board of Trustees.
6. The employer shall bear all the expenses of the administration of the Provident Fund and also make good any other loss that may be caused to the Provident Fund due to theft, burglary, defalcation, misappropriation or any other reason.
7. Any deficiency in the interest declared by the Board of Trustees is to be made good by the employer to bring it up to the statutory limit.
8. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the funds as approved by the appropriate authority and as and when amended thereto along with a translation in the language of the majority of the employees.
9. The rate of contributions payable, the conditions and quantum of advances and other matters laid down under the provident fund rules of the establishment and the interest credited to the account of each member, calculated on the monthly running balance of the member and declared by the Board of Trustees shall not be lower than those declared by the Central Government under the

various provisions prescribed in the Act and the Scheme framed there under.

10. Any amendment to the Scheme, which is more beneficial to the employees than the existing rules of the establishment, shall be made applicable to them automatically pending formal amendment of the Rules of the Trust.
11. No amendment in the rules shall be made by the employer without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner (referred to as RPFC hereafter). The RPFC shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
12. All claims for withdrawals, advances and transfers should be settled expeditiously, within the maximum time frame prescribed by the Employees' Provident Fund Organization.
13. The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited, withdrawal and interest in respect of each employee. The maintenance of such records should preferably be done electronically. The establishments should periodically transmit the details of members' accounts electronically as and when directed by the CPFC/ RPFC.
14. The Board of Trustees shall issue an annual statement of accounts or pass books to every employee within six months of the close of financial/ accounting year free of cost once in the year. Additional printouts can be made available as and when the members want, subject to nominal charges. In case of passbook, the same shall remain in custody of employee to be updated periodically by the Trustees when presented to them.
15. The employer shall make necessary provisions to enable all the members to be able to see their account balance from the computer terminals as and when required by them.

16. The Board of Trustees and the employer shall file such returns monthly/ annually as may be prescribed by the Employees' Provident Fund Organization within the specified time-limit, failing which it will be deemed as a default and the Board of Trustees and employer will jointly and separately be liable for suitable penal action by the Employees' Provident Fund Organization.
17. The Board of Trustees shall invest the monies of the provident fund as per the directions of the Government from time to time. Failure to make investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees separately and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his representative.
18. (a) The securities shall be obtained in the name of Trust. The securities so obtained should be in dematerialized (DEMAT) form and in case the required facility is not available in the areas where the trust operates, the Board of Trustees shall inform the Regional Provident Fund Commissioner concerned about the same.

(b) The Board of Trustees shall maintain a script wise register and ensure timely realization of interest.

(c) The DEMAT Account should be opened through depository participants approved by Reserve Bank of India and Central Government in accordance with the instructions issued by the Central Government in this regard.

(d) The cost of maintaining DEMAT account should be treated as incidental cost of investment by the Trust. Also all types of cost of investments like brokerage for purchase of securities etc. shall be treated as incidental cost of investment by the Trust.

19. All such investments made, like purchase of securities and bonds, should be lodged in the safe custody of depository participants, approved by Reserve Bank of India and Central Government, who shall be the custodian of the same. On closure of establishment or liquidation or cancellation of exemption from EPF Scheme, 1952, such custodian shall transfer the investment obtained in the name of the Trust and standing in its credit to the RPFC concerned directly on receipt of request from the RPFC concerned to that effect.
20. The exempted establishment shall intimate to the RPFC concerned the details of depository participants (approved by Reserve Bank of India and Central Government), with whom and in whose safe custody, the investments made in the name of trust, viz., Investments made in securities, bonds, etc. have been lodged. However, the Board of Trustees may raise such sum or sums of money as may be required for meeting obligatory expenses such as settlement of claims, grant of advances as per rules and transfer of member's P.F. accumulations in the event of his/ her leaving service of the employer and any other receipts by sale of the securities or other investments standing in the name of the Fund subject to the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner.
21. Any commission, incentive, bonus, or other pecuniary rewards given by any financial or other institutions for the investments made by the Trust should be credited to its account.
22. The employer and the members of the Board of Trustees, at the time of grant of exemption, shall furnish a written undertaking to the RPFC in such format as may be prescribed from time to time, inter alia, agreeing to abide by the conditions which are specified and this shall be legally binding on the employer and the Board of Trustees, including their successors and assignees, or such conditions as may be specified later for continuation of exemption.

3194 GI/03-3

23. The employer and the Board of Trustees shall also give an undertaking to transfer the funds promptly within the time limit prescribed by the concerned RPFC in the event of cancellation of exemption. This shall be legally binding on them and will make them liable for prosecution in the event of any delay in the transfer of funds.
24. (a) The account of the Provident Fund maintained by the Board of Trustees shall be subject to audit by a qualified independent chartered accountant annually. Where considered necessary, the CPFC or the RPFC in-charge of the Region shall have the right to have the accounts re-audited by any other qualified auditor and the expenses so incurred shall be borne by the employer.
- (b) A copy of the Auditor's report along with the audited balance sheet should be submitted to the RPFC concerned by the Auditors directly within six months after the closing of the financial year from 1st April to 31st March. The format of the balance sheet and the information to be furnished in the report shall be as prescribed by the Employees' Provident Fund Organization and made available with the RPFC Office in electronic format as well as a signed hard copy.
- (c) The same auditors should not be appointed for two consecutive years and not more than two years in a block of six years.
25. A company reporting loss for three consecutive financial years or erosion in their capital base shall have their exemption withdrawn from the first day of the next/ succeeding financial year.
26. The employer in relation to the exempted establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3) of

section 17 of the Act within 15 days from the close of every month.

27. In the event of any violation of the conditions for grant of exemption, by the employer or the Board of Trustees, the exemption granted may be cancelled after issuing a show cause notice in this regard to the concerned persons.
28. In the event of any loss to the trust as a result of any fraud, defalcation, wrong investment decisions etc. the employer shall be liable to make good the loss.
29. In case of any change of legal status of the establishment, which has been granted exemption, as a result of merger, demerger, acquisition, sale, amalgamation, formation of a subsidiary, whether wholly owned or not, etc., the exemption granted shall stand revoked and the establishment should promptly report the matter to the RPFC concerned for grant of fresh exemption.
30. In case, there are more than one unit/ establishment participating in the common Provident Fund Trust which has been granted exemption, all the trustees shall be jointly and separately liable/ responsible for any default committed by any of the trustees/ employer of any of the participating units and the RPFC shall take suitable legal action against all the trustees of the common Provident Fund Trust.
31. The Central Government may lay down any further conditions for continuation of exemption of the establishments”.

[F. No. S-35016/01/2002-SS.-II]

D.S. POONIA, Jt. Secy.

Note :—The Employees' Provident Funds Scheme, 1952 has been amended from time to time, the last amendment thereof was notified vide No. G.S.R. 783(E) dated 6-10-2003 in the Gazette of India.